भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4560
उत्तर देने की तारीख 20 अगस्त, 2025

केरल में मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी

4560. **श्री बैन्नी बेहनन:**
क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जनजातीय, पहाड़ी और वन-आसन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से पर्यटन क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान की है, जहाँ अभी भी मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में कम सेवाएँ उपलब्ध हैं अथवा सुविधा अनुपलब्ध है;

(ख) यदि हाँ, तो इन कमियों को दूर करने के लिए जारी या प्रस्तावित पहलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को केरल में अथिरापिल्ली, मलक्कापारा, वझाचल, पोंगिनचोड़, साइलेंट वैली, गवी और वायनाड एवं इडुक्की के कुछ हिस्सों जैसे जनजातीय और पर्यटन क्षेत्रों में संचार सेवाओं में गंभीर कमियों की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन क्षेत्रों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, आपदा-रोधी और समावेशी दूरसंचार अवसंरचना प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ), भारतनेट या 4जी संतृप्ति परियोजना के अंतर्गत कोई विशेष पैकेज या योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ) जून 2025 तक देश के 6,44,131 गांवों में से (भारत के महारजिस्ट्रार के आंकड़ों के अनुसार) 6,30,582 गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से कवर किया गया है और इनमें से 6,25,571 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी है। केरल के सभी 1,438 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी

है, जिसमें अथिरापिल्ली, मलक्कापारा, वझाचल, पोंगिनचुवाडु, साइलेंट वैली और गवी जैसे पर्यटन स्थल शामिल हैं।

सेवा से वंचित किसी भी बसे हुए गांव के लिए मोबाइल कवरेज तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा प्रदान की जाती है। सरकार डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) से वित्त पोषण के माध्यम से देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में 4जी मोबाइल टावरों की संस्थापना के माध्यम से दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए विभिन्न स्कीमों को लागू कर रही है। आज की तारीख तक केरल में विभिन्न डीबीएन वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत 502 गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए 317 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं।

भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड सेवाओं जैसे वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन आदि के लिए कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रिंग टोपोलॉजी में देश में सभी ग्राम पंचायतों के लिए कनेक्टिविटी के प्रावधान के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जिसमें मौजूदा नेटवर्क का उन्नयन और मांग के आधार पर लगभग 3.8 लाख बिना ग्राम पंचायतो वाले गांवों में कनेक्टिविटी प्रदान करना शामिल है। केरल में सभी 978 ग्राम पंचायतों को भारतनेट परियोजना के तहत सेवा प्रदान करने के लिए तैयार कर दिया गया है।

*****